महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परिवार के साथ मुख्यमंत्री निवास में बने राजराजेश्वरी माता के मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना की। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शर्मा ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और आरती उतारी। मुख्यमंत्री निवास पर तैनात अधिकारी व कर्मचारी भी इस दौरान मौजूद थे।

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश, गवाही के लिए उम्र की सीमा नहीं होती

- **सुप्रीम कोर्ट ने कहा एविडैंस एक्ट में गवाह की न्यूनतम आयु नहीं दी गई है इसलिए बच्चे की गवाही भी मान्य।**
- **सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए 7 साल की बच्ची की गवाही के आधार पर आरोपी को पत्नी की हत्या का दोषी करार दिया।**

नई दिल्ली, 26 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि बच्चे की गवाही भी किसी अन्य गवाह की तरह ही मान्य है। शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई। यह मामला खास इसलिए है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल की बच्ची की गवाही को आधार बनाया, जिसने अपनी मां की हत्या होते देखी थी। सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया कि गवाह के लिए कोई न्यूनतम उम्र नहीं होती और बच्ची के बयान को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह 7 साल की है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बच्चे के बयान की जांच सावधानी से करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें आसानी से प्रभावित किया जा सकता है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने एमपी हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। हाईकोर्ट ने बच्ची के बयान को खारिज कर दिया था और आरोपी को बरी कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एविडेंस एक्ट में गवाह की न्यूनतम उम्र तय नहीं है। इसलिए, बच्ची की गवाही को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर बच्चा गवाही देने के लिए सक्षम है, तो उसकी गवाही किसी अन्य गवाह की तरह ही मानी जाएगी। लेकिन, अदालत को बच्चे के बयान की जांच बहुत ध्यान से करनी चाहिए। ऐसा इसलिए, क्योंकि बच्चे जल्दी बहकावे में आ सकते हैं।

सर्वोच्च कोर्ट ने आगे कहा कि इसका मतलब यह नहीं कि छोटी-सी गलती पर बच्चे की गवाही को खारिज कर दिया जाए। बल्कि, बच्चे के बयान को बहुत सावधानी से परखा जाना चाहिए। इस मामले में, सर्वोच्च कोर्ट ने बच्ची की गवाही को विश्वसनीय मानते हुए उसके पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई। यह फैसला भविष्य में ऐसे मामलों में एक मिसाल का काम करेगा। ये निर्णय बच्चों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों की आवाज भी सुनी जाए और उन्हें न्याय मिले। यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया में बच्चों की भूमिका को मजबूत करता है।

50 लाख डॉलर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

खरीद कर अमीर लोग अमेरिका आ सकते है।

ट्रम्प ने कहा कि गोल्ड कार्ड की बाकी जानकारी दो सप्ताह में दी जा सकेगी। जब एक पत्रकार ने पूछा कि क्या रूस के अमीर भी यह कार्ड खरीद सकते है तो ट्रम्प ने कहा, "यह संभव है, मैं रूस के कुछ अमीरों को जानता हूँ, जो बहुत अच्छे हैं।"

ट्रम्प के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड ल्यूटनिक ने पत्रकारों से कहा कि वर्तमान ईबी-5 वीसा कार्यक्रम बकवास और फ्रॉड है, इसके तहत ग्रीन कार्ड प्राप्त करना बहुत सस्ता था। ल्यूटनिक ने कहा, इसलिए राष्ट्रपति ने कहा, ऐसे बकवास कार्यक्रम को खत्म कर देना ही बेहतर है। हम इसकी जगह ट्रम्प गोल्ड कार्ड लाएंगे।

सी.एन.एन. रिपोर्ट के अनुसार, ईबी-5 वीसा कार्यक्रम का इस्तेमाल कर राष्ट्रपति ट्रम्प के परिवार ने कई प्रॉपर्टी डैवलपमैंट में इसका फायदा उठाया था। ट्रम्प के पहले कार्यकाल में इस कार्यक्रम की आलोचना हुई थी और तब इसमें सुधार का सुझाव दिया गया।

ईबी-5 वीसा कार्य को 2022 में जो बाइडेन के कार्यकाल में आखिरी बार रिव्यू किया गया था और निवेश की आवश्यकता को बढ़ाकर वर्तमान स्तर तक लाया गया था। वर्ष 2019 में ट्रम्प प्रशासन ने आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में निवेश की सीमा बढ़ाकर 9 लाख डॉलर करने की कोशिश की थी, जिसे 2021 में फैडरल जज ने रोक दिया था।

ट्रम्प अमेरिका का मूल स्वरूप बदलना चाहते हैं, जो इम्मिग्रैंट्स के योगदान से विश्व में नम्बर वन बन जाए।

गत 400 सालों से अमेरिका पूरी दुनिया के आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है।

तीन साल बाद यूक्रेन युद्ध...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सहयोगियों के खिलाफ वोट कर रहा था, जिससे, पूरी भू-राजनीतिक तस्वीर बदल गई। रूस और अमेरिका ने ईयू के खिलाफ वोट किया। यह पहली बार है, जब अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने संयुक्त राष्ट्र में एक दूसरे के खिलाफ मतदान किया। महत्वपूर्ण यह भी है कि इस प्रस्ताव पर दो महत्वपूर्ण देश अनुपस्थित थे, जिनमें से एक रूस का "लिमिटलैस" मित्र था। अनुपस्थित रहने वाले देश हैं चीन और ईरान। अमेरिका और रूस की अचानक निकटता ने वर्षों की चीनी कूटनीति को उलट दिया, जो रूस और अमेरिका के बीच दरार डालने की कोशिश कर रही थी।

अत: अमेरिका का यूक्रेन समझौता दोहरा खेल है, तथा ऐसे कई और समझौते आने वाले हैं। यह समझौता चीन को रूस से कई मायनों में अलग कर देगा और रूस को एक प्रकार से अमेरिकी दायरे में ले आएगा। यह सत्य है कि हालांकि, चीन ने यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस को समर्थन दिया था, पर उसने रूस को चीन के जूनियर पार्टनर जैसा महसूस कराया था।

दूसरी ओर, पश्चिमी यूरोपीय देश, खासकर ई.यू. और यू.के. अब अलग-थलग पड़ गए हैं। उनका स्थायी दोस्त अब चला गया है। अमेरिका के चक्कर में इन देशों ने चीन से रिश्ते खराब कर लिए। उनके पास अब कोई सुरक्षा ताकत नहीं बची है, और वे रूस की दया के मोहताज हो गए हैं। लेकिन, फ्रांस ने कुछ कूटनीतिक जीत हासिल की है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति, एमानुएल मैक्रां ने कल वाइट हाउस में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प का कद कम कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में छाए रहे और उन्होंने कई बार ट्रम्प को सही किया। मैक्रां ने उस समय आसानी से ट्रम्प को मात दी, जब ट्रम्प ने कहा कि यूरोप ने वास्तव में यूक्रेन की रक्षा के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया, जितना अमेरिका ने किया। तब मैक्रां ने दृढ़ता से हस्तक्षेप किया और यह स्पष्ट किया कि यूक्रेन की रक्षा के लिए ईयू ने धन प्रदान किया था: "पैसा, असली पैसा"। तब ट्रम्प चुप हो गए। वाइट हाउस के अनुभवी संवाददाताओं ने बताया कि पहली बार ऐसा हुआ कि ट्रंप उस समय प्रैस क्रॉन्फ्रैंस में चुप रहे, जब मैक्रां अपनी बात कह रहे थे। यहाँ तक कि वाइट हाउस से बाहर आने के बाद मैक्रां ने ट्रम्प को खूब खरी खोरी सुनाई।

'दक्षिण के किसी राज्य की सीटें कम नहीं होगी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मैं हर व्यक्ति की जानकारी में यह बात ला रहा हूँ कि 2026 की जनसंख्या के आधार पर होने वाली लोकसभा क्षेत्रों के परिसीमन की कवायद बहुत ज्यादा खतरनाक है।" उन्होंने अपनी पोस्ट में पूछा, "अगर इस कारण से संसद में हमारा संख्याबल कम होता है, अगर इस कारण हमारी आवाज़ दबती है, तो यह (परिसीमन) न्यायोचित कैसे हो सकता है।"

उन्होंने लोकसभा क्षेत्रों के परिसीमन के क्रियान्वयन पर विचार-विमर्श करने के लिये 5 मार्च को एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाई हैं। उन्होंने परिसीमन को तमिलनाडु के ऊपर लटकती तलवार बताया।

शाह ने स्टालिन पर तमिलनाडु की जनता से झूठ बोलने का आरोप लगाते हुये कहा कि उनके (शाह) के आश्वासन के बाद, अब मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिये।

शाह ने तमिलनाडु सरकार पर कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार तथा शासन व्यवस्था के मुद्दों को लेकर हमला बोला और कहा, "(तमिलनाडु में) राष्ट्रविरोधी प्रवृत्तियाँ चरम पर हैं। तमिलनाडु सरकार ने 1998 के सीरियल बम-ब्लास्ट के मास्टरमाइन्ड की शव यात्रा को सुरक्षा प्रदान की थी।" शाह का संकेत एस ए बाशा की ओर था, जो 14 फरवरी 1998 को कोयम्बटूर में हुये बम-ब्लास्टों का मास्टरमाइन्ड था। इन ब्लास्टों में 58 लोग मारे गये थे।

शाह ने कहा, "राज्य में ड्रग माफिया को खुली छूट है तथा अवैध खनन माफिया ने राजनीति को भ्रष्ट कर दिया है।"

द्रमुक पर भ्रष्ट नेताओं को पार्टी की सदस्यता देने का आरोप लगाते हुये शाह ने कहा कि स्टालिन की पार्टी के नेता मनी लॉण्डरिंग, आय से ज्यादा सम्पत्ति के मामलों, बजरी-खनन तथा 2जी घोटाले तक में लिप्त हैं।

उन्होंने कहा, "कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि द्रमुक ने अपने सदस्यता-अभियान के दौरान, सभी भ्रष्ट लोगों को छाँटकर पार्टी में ले लिया है।"

शाह ने जोर देते हुये कहा कि 2026 में एनडीए राज्य में सरकार बनायेगा तथा एनडीए को "हरियाणा और महाराष्ट्र से भी ज्यादा बहुमत" मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और कर्नाटक भूमि (हस्तांतरण प्रतिबंध) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत जांच की। केंद्रीय मंत्री ने पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय में एफआईआर को चुनौती दी थी, लेकिन 2015 में उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट में की गई अपील भी जांच को रोकने में विफल रही।

पुणे : सरकारी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में खड़ी खाली बस में ले गया। अभी अंधेरा था और जैसे ही महिला बस में चढ़ी, आरोपी भी अंदर आ गया और उसके साथ दुष्कर्म कर फरार हो गया।

यूक्रेन की जमीन के नीचे दबे खनिज को अमेरिका ललचाई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

डॉनल्ड ट्रम्प और कई अमेरिकन नीति निर्माता यूक्रेन की खनिज सम्पदा को अपनी प्राथमिकता सूची में उच्च स्थान पर रखते हैं। वे इसे चीन और रुस के साथ निरंतर भू राजनैतिक संघर्ष में एक रणनीतिक "एसैट" के रुप में देखते हैं। अमेरिका इन संसाधनों पर नियंत्रण चाहता है, ताकि अपने औद्योगिक व सैन्य भविष्य को सुरक्षित रखने के साथ विरोधियों को कमज़ोर कर सके।

वॉशिंगटन की सबसे बड़ी चिन्ता खनिज सम्पदा के लिए चीन पर निर्भर होने की है, जिसका विश्व के दुर्लभ खनिज संसाधनों का 60 से 70 प्रतिशत भंडार पर नियंत्रण है और इसके विपरीत जैसा संयुक्त राष्ट्र संघ ने बताया है , यूक्रेन के पास 5 प्रतिशत भंडार है। हालांकि चीन इसमें अग्रणी है, पर यूक्रेन एक विकल्प है और अमेरिका इसकी अनदेखी नहीं कर सकता।

हालांकि, इन संसाधनों को सुरक्षित करने का रास्ता कई बाधाओं से भरा हुआ है। यूक्रेन के कई समृद्ध खनिज भंडार अब रुस के कब्जे वाले क्षेत्रों में स्थित हैं, जिससे उत्खनन करना और उसे अन्य जगह ले जाना भारी मुश्किल हो गया है। फिर भी, चुनौतियों के बावजूद, अमेरिका यूक्रेन के खनिजों को एक ऐसे स्रोत के रुप में देखता है, जो एक एकल, प्रमुख आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता को कम करने में इसकी मदद कर सकता है।

विशेष रुप से सैन्य -औद्योगिक क्षेत्र के लिए दांव बहुत ऊंचा हैं। टाइटेनियम जैसे खनिज फाइटर जेट, मिसाइल और उच्च गुणवत्ता वाले रक्षा उपकरण बनाने में अनिवार्य हैं।

वर्तमान में, अमेरिकी रक्षा क्षेत्र द्वारा इस्तेमाल किया गया अधिकांश टाइटेनियम रुस से आता है- यह एक ऐसी कमजोरी है, जिसे अमेरिकी नेता समाप्त करने के लिए उत्सुक हैं। अगर वॉशिंगटन यूक्रेन के भंडार को हासिल कर लेता है तो यह निर्भरता समाप्त हो सकती है और पश्चिमी सैन्य आपूर्ति श्रृंखलाओं पर रुस का नियंत्रण कमजोर पड़ सकता है।

यूक्रेन के लीथियम भंडार भी महत्वपूर्ण हैं। जैसे -जैसे दुनिया इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण की ओर बढ़ रही है, लीथियम की मांग बढ़ गई है। ईवी बाजार पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए अमेरिका व चीन में दौड़ है, और यूक्रेन के लीथियम भंडार तक पहुंच हासिल करना अमेरिका की बैटरी उत्पादन क्षमता को मजबूत कर सकता है, जो बीजिंग के वर्चस्व को चुनौती दे सकता है।

यूक्रेन के खनिजों पर नियंत्रण से अमेरिका को यूरोप पर आर्थिक दबदबा मिल जाएगा। वॉशिंगटन उसके सहयोगियों को कच्चे माल का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन सकता है, इससे चीन और रुस हाशिए पर जा सकते हैं।

ट्रम्प, जो हमेशा से सौदेबाजी में आगे रहे हैं, ने रुस के साथ बातचीत में यूक्रेन के संसाधनों का एक सौदे की चिप के रुप में उपयोग करने का संकेत दिया है। उन्होंने कीव को मिलने वाली अमेरिकी सहायता की आलोचना की है, यह सवाल किया कि अमेरिका को इसके बदले में क्या मिल रहा है। उनका "अमेरिका पहले" रुख यह संकेत देता है कि भविष्य की किसी भी बातचीत में, वे आर्थिक फायदे की मांग करेंगे- शायद यूक्रेन की खनिज संपत्ति तक विशेष पहुंच हासिल करने का प्रयास करें।

एक ऐसी दुनिया में जहां संसाधन ताकत को परिभाषित करते हैं, यूक्रेन के दुर्लभ खनिज सिर्फ एक प्राकृतिक खजाना नहीं हैं- वे एक भू-राजनीतिक हथियार हैं और उन पर नियंत्रण के लिए संघर्ष में, अमेरिका, चीन और रुस सभी शामिल हैं।

केजरीवाल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अरोड़ा राजनीति में आने से पहले बिजनेस टाइकून तथा बड़ी परोपकारी हस्ती थे। अगर वे लुधियाना -पश्चिम उपचुनाव जीत जाते हैं तो उन्हें राज्यमंत्री बनाकर, किसी मंत्रालय को स्वतंत्र प्रभार सौंपा जा सकता है।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908